

विधानसभा मानसून सत्र

न्यूज ब्रीफ

विधानसभा अध्यक्ष ने लिया ‘गार्ड ऑफ ऑनर’



सदन की कार्यवाही से पूर्व गार्ड ऑफ ऑनर लेते कुलदीप सिंह पठानिया ।

अनंत ज्ञान ब्यूरो, शिमला। 14वें विधानसभा के मॉनसून सत्र के 10वें दिन विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया सचिवालय पहुंचे और सलामी ली। उपस्थित सदस्यों और स्टाफ ने उनका सम्मानपूर्वक स्वागत किया और सत्र की कार्यवाही की तैयारियों का अवलोकन किया। कार्यवाही की तैयारी सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई और सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले अध्यक्ष ने आवश्यक निर्देश दिए। वहीं, राजकीय महाविद्यालय नाहन की बीएससी तृतीय वर्ष की छात्रा श्रेया शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष को कौंसिल चैंबर के बाहर उनका स्तंभ बनाया रेखा चित्र भेंट किया। अध्यक्ष ने छात्रा के प्रयास की सराहना की और उसे प्रेरित किया कि इसी प्रकार अपने सुजनत्मक प्रयासों को जारी रखे। उपर, सत्र अरंभ होने से पूर्व शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने पठानिया से उनके कार्यालय कक्ष में शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात में शिक्षा और युवा विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। अध्यक्ष ने मंत्री के प्रयासों की प्रशंसा की और दोनों पक्षों के सहयोग को सुनिश्चित करने की बात कही। मानसून सत्र के 10वें दिन पठानिया ने सदन की कार्यवाही का संचालन किया। सदस्यों ने सक्रियता और अनुशासन के साथ अपने विचार रखे और प्रस्तावों पर चर्चा की।

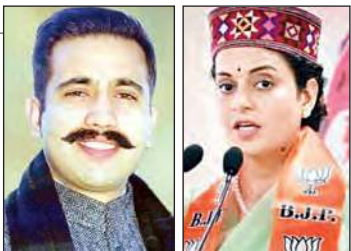
राजस्व प्रबंधन पोर्टल पर कर सकेंगे मुआवजे के लिए आवेदन : कृषि मंत्री

अनंत ज्ञान ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में कृषि एवं पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने बताया कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को राज्य सरकार अन्य राज्यों की तुलना में अधिक मुआवजा दे रही है। उन्होंने कहा कि मकानों के ध्वस्त होने और मवेशियों की मौत जैसे मामलों में प्रभावित लोग उपायुक्त कार्यालय के माध्यम से राजस्व प्रबंधन सिस्टम पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। उपायुक्तों को मुआवजा देने के अधिकार प्रदान किए गए हैं। यह जानकारी मंत्री ने शाहपुर से विधायक कैवल सिंह पठानिया द्वारा नियम 62 के तहत बिजली गिरने से हुए नुकसान पर लाए गए ध्यानकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए दी। मंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब तक 1081 छोटे-बड़े पशुओं की मौत दर्ज की जा चुकी है और लगभग 14 लाख रुपये का नुकसान राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पोर्टल पर दर्ज हुआ है। उन्होंने बताया कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के धारकंडी इलाके के कोटधार में बिजली गिरने से 120 भेड़-बकरियों की मौत हुई है। इससे पहले विधायक कैवल सिंह पठानिया ने कहा कि भारी बारिश और बिजली गिरने से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि मुआवजा दिलाने के लिए पटवारी, पशुपालन अधिकारी और पुलिस की रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है, जबकि पशुओं का पोस्टमार्टम कराने में दो-तीन दिन लग जाते हैं। ऐसे में किसानों को समय पर राहत नहीं मिल पाती। पठानिया ने विधानसभा में यह भी मांग रखी कि मुआवजे की प्रक्रिया में ग़ाम प्रधान की रिपोर्ट को भी आधार माना जाए।

लोक निर्माण मंत्री ने कंगना रनौत के रिलीफ फंड दावे पर निशाना साधा

अनंत ज्ञान ब्यूरो, शिमला

हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बॉलीवुड अभिनेत्री व सांसद कंगना रनौत के हिमाचल को 2200 करोड़ रुपए के रिलीफ फंड मिलाने के दावे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर कंगना के बयान को निराधार बताते हुए उसे जनता को भ्रमित करने वाला करार दिया।



विक्रमादित्य सिंह ने दी तीखी प्रतिक्रिया, सोशल मीडिया पर सुर्खियों में

कंगना रनौत ने दो दिन पहले दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान दावा किया था कि हिमाचल प्रदेश को 2200 करोड़ रुपए का रिलीफ फंड दिया गया है। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर तीखी बहस छिड़ गई और यूजर्स ने कंगना के दावे पर विवादित प्रतिक्रियाएं दीं। राज्य सरकार के अधिकारियों

ने कंगना के दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस तरह का कोई भी आधिकारिक आंकड़ा मौजूद नहीं है। गौरतलब है कि हिमाचल भाजपा ने पहले अपने एक्स सोशल मीडिया अकाउंट पर कंगना के बयान को साझा किया था, लेकिन बाद में यह पोस्ट हटा दी गई।

जीएसटी संशोधन सर्वसम्मति से मंजूर

हंगामे व अहम बिलों के बीच गरमाया सत्र, पुनर्नियोजन और पेंशन पर विपक्ष का हमला

सत्यदेव भारद्वाज, अनंत ज्ञान ब्यूरो

शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का दसवां दिन कई अहम मुद्दों और तीखी बहसों का गवाह बना। सत्र के दौरान एक ओर जहां सदन ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम, 2017 में दूसरे संशोधन को मंजूरी देकर ‘एक राष्ट्र, एक कर’ की दिशा में कदम बढ़ाया। वहीं, विपक्ष ने पुनर्नियोजन और एचआरटीसी पेंशन में देरी के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कड़ा विरोध जताया। दिनभर सदन में आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलता रहा, जिसके बीच विधानसभा अध्यक्ष ने बारिश से प्रभावित राजमार्गों और टोल माफी के मुद्दे पर उच्चस्तरीय समिति की बैठक बुलाने की घोषणा भी की।

मुख्यमंत्री सुखविंद सिंह सुक्खू की अनुपस्थिति में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में जीएसटी संशोधन विधेयक पेश किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह संशोधन केंद्र सरकार और जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर आधारित

टोल माफी व आपदा क्षति पर उच्च स्तरीय बैठक का ऐलान



उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सदन में अपना वक्तव्य देते हुए।

है, जिससे राज्यों में कराधान की एकरूपता सुनिश्चित होगी। नौ धाराओं में संशोधन और छह नए प्रावधानों के साथ यह कानून अब अधिक पारदर्शी और डिजिटल अनुपालन के अनुकूल होगा। विपक्ष सहित सभी दलों ने विधेयक का समर्थन करते हुए इसे सर्वसम्मति से

सदन में तीखी बहसों के बीच सरकार का बचाव

पारित किया।

विधानसभा का माहौल तब गरमा गया, जब भाजपा विधायकों ने सरकार पर आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में अधिकारियों को पुनर्नियोजित किया जा रहा है, जबकि एचआरटीसी कर्मचारियों को वेतन और पेंशन समय पर नहीं

नगर निगम संशोधन विधेयक, संस्थानों को बंद करने और अभद्र टिप्पणियों पर उठे सवाल

अनंत ज्ञान ब्यूरो, शिमला

पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस खुलेआम संविधान का उल्लंघन कर रही है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश नगर निगम संशोधन विधेयक 2025 को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए और इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243



हिमाचल सरकार पर जयराम ठाकुर का तीखा हमला

हटया जाता है, जिससे छात्रों का नामांकन घट जाता है, और फिर उसी कारण का हवाला देकर स्कूलों को बंद कर दिया जाता है। उन्होंने बताया कि सरकार ने सत्ता में आते ही 2000 से ज्यादा संस्थानों को बंद कर दिया, जबकि अभी तक कैबिनेट का भी गठन नहीं हुआ था।

विपक्षी गठबंधन की टिप्पणियां उनकी कुंठ का प्रतीक

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विपक्षी गठबंधन के नेताओं, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई अभद्र टिप्पणियों की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि बिहार में आयोजित एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री की दिवंगत माता के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करना बेहद निंदनीय है।

अनंत ज्ञान ब्यूरो, शिमला

हिमाचल प्रदेश में सरकार द्वारा 10 सेस लगाए जा रहे हैं। इन सेस के माध्यम से अभी तक 762.13 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व एकत्र किया गया है। इनमें से पांच सैंस पूर्व सरकार के समय के हैं और वर्तमान सरकार ने भी पांच और सेस लगाए हैं। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने वीरवार को यहां विधायक विक्रम ठाकुर के एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जो सेस एकत्र करती है, उसे उसी मद पर खर्च किया जाता है, जहां के लिए सेस लगाया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार इसके लिए जल्द ही एसओपी तैयार कर रही है। इसके तहत विभाग अपने स्तर पर ही सेस की राशि को खर्च

शिक्षा मंत्री बोले-स्वारघाट कॉलेज के फंड डायवर्ट मामले की होगी समीक्षा

अनंत ज्ञान ब्यूरो, शिमला

हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने नयना देवी के स्वारघाट कॉलेज के फंड डायवर्ट करने के मामले पर स्पष्ट किया कि सरकार इस मामले की पूरी समीक्षा करेगी। उन्होंने सदन को बताया कि किसी भी प्रकार की अनियमितता की जानकारी मिलने पर संबंधित एजेंसी लोक निर्माण विभाग कार्रवाई करेगी। विद्यार्थियों और शैक्षणिक संस्थानों के हित में प्रत्येक कदम उठाया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कॉलेज के विकास कार्य बाधित न हों।

कांग्रेस विधायक भवानी सिंह पठानिया ने शून्यकाल में सदन में वजीर राम सिंह पठानिया को स्वतंत्रता सेनानी घोषित करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि 24 साल की उम्र में वीर योद्धा ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई और गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। शाहपुर के कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया ने भी वजीर राम सिंह के योगदान को याद किया और कहा कि उनके पर लोकगाथाएं बनी हैं। ज्वालामुखी के कांग्रेस विधायक संजय रतन ने सदन में कहा कि ऐसे योद्धाओं

को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा अवश्य दिया जाना चाहिए।

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि वजीर राम सिंह पठानिया जैसी महान विभूतियों को श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सुझाव दिया कि इस

मामले पर सदन में संकल्ला लाकर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाए।

लाहौल-स्पीति की कांग्रेस विधायक अनुराधा राणा ने अग्निवीर अरुण कुमार के परिवार को आर्थिक सहायता देने, उनके नाम से सड़क का नामकरण और उनके परिजनों को नौकरी देने की मांग की। इस पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उचित कदम उठाएगी।

बुद्धी के विधायक रामकुमार ने नया बस अड्डा बनाने का मामला उठाया, जिस पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह शहरी विकास और अन्य एजेंसी के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। इंंदौरा के विधायक मलेंद्र राजन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत राशि देने की मांग की, जिस पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राहत कार्यों के लिए प्रतिबद्ध है।

हिमाचल प्रदेश में लग रहे 10 तरह के सेस

अनंत ज्ञान ब्यूरो, शिमला

हिमाचल प्रदेश में सरकार द्वारा 10 सेस लगाए जा रहे हैं। इन सेस के माध्यम से अभी तक 762.13 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व एकत्र किया गया है। इनमें से पांच सैंस पूर्व सरकार के समय के हैं और वर्तमान सरकार ने भी पांच और सेस लगाए हैं। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने वीरवार को यहां विधायक विक्रम ठाकुर के एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जो सेस एकत्र करती है, उसे उसी मद पर खर्च किया जाता है, जहां के लिए सेस लगाया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार इसके लिए जल्द ही एसओपी तैयार कर रही है। इसके तहत विभाग अपने स्तर पर ही सेस की राशि को खर्च

कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि अभी इसका पेसा वित्त विभाग के पास होता है, लेकिन वित्त विभाग अपनी मर्जी से इस राशि को खर्च नहीं कर सकता।

विधायक विक्रम ठाकुर ने कहा कि सरकार आम लोगों पर 10 प्रकार के सेस लगा रही है और इसके प्रतिशत के बारे में पूछा। उन्होंने कोविड सेस और एंबुलेंस सेवा सेस को लेकर सवाल उठाए। विधायक

क्या होता है सेस

सेस एक विशेष कर (टैक्स) होता है जो सरकार द्वारा किसी विशेष उद्देश्य जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य या स्वच्छता के लिए लगाया जाता है। यह मुख्य रूप से अतिरिक्त होता है और इसका उपयोग केवल उसी निर्धारित उद्देश्य के लिए किया जाता है, जैसे शिक्षा सेस या स्वच्छ भारत सेस।

डिप्टी सीएम ने सेस से प्राप्त धनराशि का ब्योरा

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि पंचायतीराज संस्था सेस से वर्ष 1998-99 से 2022-23 तक कुल 1,53,57,58,045 रुपए प्राप्त हुए, जिसमें 64,97,97,653 रुपए शहरी स्थानीय निकायों को और 88,59,60,392 रुपए पंचायतीराज संस्थाओं को आवंटित किए गए। मोटर वाहन सेस से वर्ष 2017 से 2025 तक 185,13,64,000 रुपए प्राप्त हुए। शराब की बिक्री पर लगाए गए गोवंश विकास निधि से वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक 65,35,61,484 रुपए प्राप्त हुए। कोविड सेस से वर्ष 2020-2021 से 2023-24 तक 1,45,12,53,032 रुपए प्राप्त हुए। लेबर सेस, मिल्क सेस और पसेवर्णन सेस से भी राज्य को करोड़ों की राशि प्राप्त हुई।

सीएम के निर्देश पर तीन बसें हुई रवाना

अनंत ज्ञान ब्यूरो, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंद सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार चंबा जिला प्रशासन ने श्री मणिमहेश यात्रा के दौरान भारी बारिश से

प्रभावित श्रद्धालुओं की सुरक्षित वापसी के लिए त्वरित कार्रवाई की। कलसुई से पठानकोट की ओर तीन बसें रवाना की गईं, जिनमें लगभग 150 श्रद्धालु सवार थे। प्रशासन ने इस कदम से यात्रियों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राहत और बचाव कार्य लगातार जारी हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि हिमाचल सरकार और जिला प्रशासन पूरी तत्परता के साथ प्रभावित लोगों की सहायता में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री की सक्रिय निगरानी और प्रशासन की तत्परता से यात्रियों में सुरक्षा और भरोसे की भावना मजबूत हुई है।

नगर निकाय चुनाव जल्द करवाए जाएं: आशीष शर्मा

अनंत ज्ञान ब्यूरो, शिमला। हिमाचल विधानसभा में नगर निकाय चुनावों को दो साल के लिए टालने संबंधी नगरपालिका संशोधन विधेयक पेश किया गया। इस पर हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने और हार के डर से चुनाव टाल रही है।

उन्होंने विधानसभा में साफ कहा कि जनता की सुविधा के लिए निकाय चुनाव समय पर होना जरूरी है। आशीष शर्मा ने जोर देकर कहा कि नगर निकायों को प्रतिनिधि मिलने चाहिए ताकि आम लोग अपने कार्यों के लिए बार-बार भटकने को मजबूर न हों। उन्होंने सरकार को चेताते हुए कहा कि चुनाव टालने से जनता की परेशानियां बढ़ेंगी और जमीनी हकीकत भी उजागर हो जाएगी। विधायक ने मांग की कि सरकार जल्द से जल्द नगर निकाय चुनाव करवाए ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रभावित न हो।

लोकतंत्र का भविष्य उज्ज्वल: पठानिया



विधानसभा परिसर में स्टूडेंट्स और टीचर्स के साथ कुलदीप सिंह पठानिया सामूहिक चित्र में।

अनंत ज्ञान ब्यूरो, शिमला

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में एक प्रेरणादायक दिन रहा। स्नातकोत्तर महाविद्यालय नाहन, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला समरहिल, दयानंद पब्लिक स्कूल शिमला, राजकीय महाविद्यालय जुखाला जिला विलासपुर और शाहीर वेद प्रकाश राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बियाचडी के 280 से अधिक छात्र-छात्राओं ने सदन की कार्यवाही का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया से मुलाकात की, जिसने इस अनुभव को और भी खास बना दिया।

कौंसिल चैंबर के बाहर हुई इस मुलाकात में छात्रों ने संसदीय प्रणाली, संवैधानिक व्यवस्था, स्पीकर के पद के महत्व और सदन संचालन में उनकी भूमिका पर कई

चंबा के लिए रवाना हुए पठानिया

इस महत्वपूर्ण संवाद के बाद पठानिया ने छात्रों को सदन की कार्यवाही देखने के लिए आमंत्रित किया। दोपहर 2.45 बजे वे जिला चंबा के लिए रवाना हुए, जहां वे भारी वर्षा से हुए नुकसान का जायजा लेंगे। वह एक सितंबर को वापस शिमला लौटेंगे और दोपहर 2 बजे से आरंभ होने वाली सदन की कार्यवाही का संचालन करेंगे।

सवाल पूछें। पठानिया ने उनके सभी प्रश्नों का विस्तार से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह एक सुखद पल है कि आज के युवा और छात्र संसदीय प्रणाली और संसदीय प्रक्रिया को जानने के लिए आकर्षित हो रहे हैं। यही भारत के लोकतंत्र की शक्ति है और यही इसे दुनिया का सबसे बड़ा और मजबूत लोकतंत्र बनाता है।

प्रश्नकाल

सदन में एक्सटेंशन और री-इंफ्लायमेंट पर विपक्ष का सवाल, डिप्टी सीएम का जवाब

अधिकारियों-कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति पर बहस

सत्यदेव भारद्वाज, अनंत ज्ञान ब्यूरो

शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में शुक्रवार को अधिकारियों-कर्मचारियों को एक्सटेंशन और री-इंफ्लायमेंट देने का मुद्दा जोर पकड़ गया। प्रश्नकाल में भाजपा के चार विधायकों ने इस संबंध में सरकार से स्पष्टीकरण मांगा। सतपाल सिंह सती और विक्रम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार इस मामले में जानकारी छिपा रही है।

सती ने कहा कि राज्य सरकार कई अधिकारियों को पुनर्नियुक्ति दे रही है, जबकि एचआरटीसी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को समय पर वेतन और पेंशन भी नहीं

संस्थान बंद करने को लेकर पक्ष-विपक्ष में नोक-झोंक

सदन में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के बीच संस्थान बंद करने को लेकर तीखी नोक-झोंक हुई। भाजपा का आरोप था कि सरकार ने पिछले तीन सालों में केवल पूर्व सरकार द्वारा खोले गए संस्थानों को बंद करने का काम किया है। सत्र में मुख्यमंत्री सुखविंद सिंह सुक्खू, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह उपस्थित नहीं थे। वहीं, स्पीकर का भी चंबा-भरमौर जाने का कार्यक्रम था, लेकिन वे उपस्थित रहे।

मिल रही। उन्होंने कहा कि पेंशनभोगियों को हर महीने अपने बकाया भुगतान के लिए बैचेंनी से इंतजार करना पड़ता है और सरकार को प्राथमिकताएं गलत दिशा में हैं। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने सदन को बताया कि इस संबंध

मामले को उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन जोर देकर कहा कि सरकार नियमित भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अग्निहोत्री ने स्पष्ट किया कि पेंशन में देरी के मामलों को वित्त विभाग के समक्ष उठाया जा रहा है और इसे जल्द हल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सभी एचआरटीसी कर्मचारियों की पेंशन 29 अगस्त को जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि दोनों मुद्दों को एक-दूसरे से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए और सरकार वित्त विभाग के साथ मिलकर भुगतान प्रणाली को सुधारने और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है।

में जानकारी बहुत व्यापक है और उसे इकट्ठा करने में समय लगेगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि जैसे ही आवश्यक सूचना उपलब्ध होगी, वह सदन के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। एचआरटीसी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में हुई देरी के

